Pariksha Saathi — दैनिक करंट अफेयर्स

6 नवंबर 2026 • हिंदी

SSC CGL • CHSL • MTS • IBPS PO/Clerk • SBI PO/Clerk • RRB — 9 खबरें + 5 प्रश्न • स्रोत: PIB (सभी खबरें आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों से)

1 भारत और म्यांमार ने चेन्नई में पहले त्रि-सेवा संयुक्त मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास 'राहत मित्र' की शुरुआत की

India and Myanmar commence their first tri-services joint Humanitarian Assistance and Disaster Relief exercise 'Rahat Mitra' at Chennai

SSC • Railway • Defence • General

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारत और म्यांमार ने 5 नवंबर 2026 को चेन्नई में पहले द्विपक्षीय त्रि-सेवा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (एचएडीआर) अभ्यास 'राहत मित्र' की शुरुआत की; यह अभ्यास 5 से 6 नवंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। 'टुगेदर फॉर ह्यूमैनिटी, स्ट्रॉन्गर थ्रू पार्टनरशिप' (Together for Humanity, Stronger through Partnership) थीम पर आधारित इस अभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना, आपसी विश्वास बढ़ाना और दोनों देशों के रक्षा बलों के बीच समन्वय को बेहतर बनाना है। मंत्रालय के अनुसार यह पहला अभ्यास भारत और म्यांमार के रक्षा बलों को पेशेवर आदान-प्रदान, अनुभव साझा करने और एचएडीआर अभियानों में अंतर-संचालन क्षमता बढ़ाने का मंच देता है, और इसमें दोनों देशों की तीनों सेनाओं के 300 से अधिक कार्मिक भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास भारतीय नौसेना के तत्वावधान में समन्वित किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि यह अभ्यास भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति और 'महासागर' (क्षेत्रीय सुरक्षा एवं विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति - MAHASAGAR) के रणनीतिक दृष्टिकोण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, और शांति एवं स्थिरता बनाए रखने तथा संकट के समय मानवीय सहायता प्रदान करने के दोनों देशों के साझा संकल्प को और मजबूत करेगा।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2333709

2 अंडमान और निकोबार कमान के तत्वावधान में पहला बिम्सटेक समुद्री सुरक्षा अभ्यास श्री विजय पुरम में संपन्न

Maiden BIMSTEC Maritime Security Exercise culminates at Sri Vijaya Puram under the aegis of the Andaman and Nicobar Command

SSC • Railway • Defence • General

पहला बिम्सटेक समुद्री सुरक्षा अभ्यास 3 नवंबर 2026 को श्री विजय पुरम में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ; इससे पहले 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2026 तक अंडमान और निकोबार कमान (एएनसी) के तत्वावधान में कई गतिविधियां और समन्वित समुद्री अभ्यास किए गए। रक्षा मंत्रालय की अंग्रेज़ी रिलीज़ एएनसी को भारत की एकमात्र परिचालन क्वाड सर्विस (चार-सेवा) कमान बताती है (हिंदी रिलीज़ में इसे त्रि-सैन्य कमान कहा गया है); इसका नेतृत्व कमांडर-इन-चीफ वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी कर रहे हैं। अभ्यास में बिम्सटेक सदस्य देशों के नौसैनिक जहाज़ों ने भाग लिया: भारतीय नौसेना के पोत आईएनएस तारागिरी, आईएनएस कर्मुक और आईएनएस सरयू, म्यांमार नौसेना का पोत यूएमएस किंग आंग ज़ेया और श्रीलंका नौसेना का पोत एसएलएनएस गजाबाहु। उपस्थित लोगों में बिम्सटेक के महासचिव श्री इंद्र मणि पांडे, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक वाइस एडमिरल बिस्वजीत दासगुप्ता (सेवानिवृत्त) तथा म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश के प्रतिनिधि शामिल थे, जिनमें बांग्लादेश के पोत बीएनएस प्रोटोय के कमांडिंग ऑफिसर भी थे। मंत्रालय के अनुसार यह अभ्यास 'दिल्ली घोषणा' की भावना के अनुरूप और नवंबर 2025 में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर आयोजित चौथी बिम्सटेक विशेषज्ञ समूह बैठक के निष्कर्षों को आगे बढ़ाते हुए आयोजित किया गया। श्री विजय पुरम में बंदरगाह चरण में उच्चस्तरीय बैठकें, पेशेवर संवाद और सांस्कृतिक आदान-प्रदान हुए, और 2 से 3 नवंबर 2026 तक श्री विजय पुरम के निकट हुए समुद्री चरण में समन्वित समुद्री तैनाती और संयुक्त परिचालन गतिविधियां शामिल रहीं। मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास का सफल समापन बिम्सटेक सदस्य देशों के बीच समुद्री सहयोग को संस्थागत रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और बिम्सटेक ढांचे के तहत भविष्य की संयुक्त पहलों के लिए आधार तैयार करता है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2333721

3 अमित शाह ने देहरादून में उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रदान किया; कहा, यह सम्मान पाने वाला देश का 16वाँ पुलिस बल

Amit Shah presents the President's Colour to Uttarakhand Police in Dehradun; calls it the 16th police force in the country to receive the honour

SSC • Railway • General

गृह मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 6 नवंबर 2026 को देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रपति निशान (President's Colour) प्रदान किया। अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस यह सर्वोच्च सम्मान पाने वाला देश का 16वाँ पुलिस बल बन गई है, और राष्ट्रपति निशान प्राप्त करना किसी भी बल के लिए तथा राज्य की स्थापना के बाद के 25 वर्षों में उत्तराखंड पुलिस में सेवा दे चुके सभी लोगों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि बल के जवानों और अधिकारियों ने 'कर्म सत्यम् शौर्यम्' के तीन सूत्रों को अपने जीवन और कर्तव्य का आधार बनाया है, और उन्होंने सर्वोच्च बलिदान देने वाले उत्तराखंड पुलिस के 206 जवानों को श्रद्धांजलि दी। श्री शाह के अनुसार यह बल 13,000 जवानों से बढ़कर 26,000 से अधिक कार्मिकों का हो गया है, इसने एसडीआरएफ के रूप में और नियमित पुलिस के रूप में जंगलों की आग, भूस्खलन और अन्य आपदाओं का सामना किया है, और सिलक्यारा सुरंग में फँसे श्रमिकों के बचाव में शौर्य दिखाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पुलिस माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण करने वाली देश की पहली राज्य पुलिस है और उसने वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में 37 पदक जीते हैं; इन खेलों का अगला संस्करण गुजरात के गांधीनगर में होना निर्धारित है। श्री शाह ने विश्वास जताया कि राष्ट्रपति निशान से बल का मनोबल बढ़ेगा।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2333753

4 खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी) सीरोटाइप सैट-1 की तैयारी पर राष्ट्रीय टेबलटॉप अभ्यास 'वज्र-सैट' का बेंगलुरु में समापन

National tabletop exercise 'VAJRA-SAT' on preparedness for foot-and-mouth disease serotype SAT-1 concludes at Bengaluru

SSC • Banking • Railway • General

पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने बेंगलुरु स्थित आईसीएआर-राष्ट्रीय पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान और रोग सूचना विज्ञान संस्थान (आईसीएआर-एनआईवीईडीआई) के समन्वय से 4-5 नवंबर 2026 को फुट-एंड-माउथ डिजीज (एफएमडी) सीरोटाइप सैट-1 की तैयारी पर दो दिवसीय राष्ट्रीय टेबलटॉप अभ्यास 'वज्र-सैट' आयोजित किया, जिसकी थीम 'डिटेक्ट अर्ली, कन्फर्म फास्ट, कंटेन टुगेदर' (जल्दी पता लगाएं, तेज़ी से पुष्टि करें, मिलकर रोकथाम करें) थी। मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने बताया कि यह अभ्यास राष्ट्रीय तैयारी और सीमा पार पशु रोगों के प्रति समन्वित प्रतिक्रिया को मजबूत करने के उद्देश्य वाली सिफारिशों के साथ संपन्न हुआ। रिलीज़ के अनुसार भारत में एफएमडी सीरोटाइप सैट-1 के मामले सामने नहीं आए हैं; अफ्रीका से आगे पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों तक इसके भौगोलिक प्रसार को देखते हुए यह अभ्यास पशुधन स्वास्थ्य, किसानों की आजीविका और पशुधन अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए एक सक्रिय तैयारी पहल के रूप में किया गया। इसमें 25 राज्यों, तीन केंद्र शासित प्रदेशों और प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों - जिनमें राज्य पशुपालन विभाग, आईसीएआर संस्थान, पशु चिकित्सा निदान प्रयोगशालाएं, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, वैक्सीन निर्माता और रक्षा एवं सीमा सुरक्षा एजेंसियां शामिल थीं - के 83 प्रतिभागी एक साथ आए, जिन्होंने रोग प्रकोप की कृत्रिम (सिम्युलेटेड) स्थितियों के माध्यम से प्रारंभिक पहचान, प्रयोगशाला पुष्टि, महामारी विज्ञान जांच, पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण, आपातकालीन टीकाकरण की तैयारी, जोखिम संचार और समन्वित प्रतिक्रिया पर विचार-विमर्श किया। अभ्यास का उद्घाटन 4 नवंबर को पशुपालन आयुक्त डॉ. नवीना बी.एम. ने किया, और 5 नवंबर को समापन सत्र की अध्यक्षता डीएएचडी के अपर सचिव (पशुधन स्वास्थ्य) श्री रमाशंकर सिन्हा ने की। 5 नवंबर 2026 को राज्यों के साथ वीर्य उत्पादन केंद्रों और वीर्य बैंकों के एफएमडी-मुक्त कंपार्टमेंटलाइजेशन पर एक अलग तकनीकी बैठक भी हुई।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2333487

5 अश्विनी वैष्णव ने दूसरे, तीसरे और चौथे स्तंभ के लिए सेमीकॉन 2.0 वेब एप्लिकेशन पोर्टल लॉन्च किया और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 12 स्वीकृत आवेदकों की घोषणा की

Ashwini Vaishnaw launches the Semicon 2.0 Web Application Portal for Pillars 2, 3 and 4 and announces 12 approved applicants under the Electronics Component Manufacturing Scheme

SSC • Banking • Railway • General

इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 6 नवंबर 2026 को 'सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत सेमीकॉन 2.0 - वेब एप्लिकेशन पोर्टल' लॉन्च किया, जिसके साथ सेमीकॉन 2.0 के दूसरे, तीसरे और चौथे स्तंभ (स्तंभ 2, 3 और 4) के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस) के तहत 12 स्वीकृत आवेदकों की घोषणा की। रिलीज़ के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के तहत 1,27,500 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी है; इसके छह स्तंभ हैं - चिप का डिजाइन, मशीनें और सामग्रियां, अधिक निर्माण इकाइयों (फैब्स) की स्थापना, एटीएमपी/ओएसएटी उद्योग को और सुदृढ़ बनाना, अनुसंधान एवं विकास, तथा प्रतिभा विकास। पहले चरण (सेमीकॉन 1.0) में छह राज्यों में 12 परियोजनाओं को 1.64 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कुल निवेश के साथ मंजूरी दी गई थी, जिनमें से पांच परियोजनाओं में अक्टूबर 2026 तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो चुका है। ईसीएमएस के तहत दी गई 12 नई मंजूरियों में 7,503 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश और 39,045 करोड़ रुपये का अनुमानित उत्पादन है, और इनसे 7,127 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है; इनमें 7 राज्यों (गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश) में 10 लक्षित सेगमेंट के उत्पाद शामिल हैं, और कॉपर फॉयल, कैथोड एक्टिव मैटेरियल और स्पेशलिटी सिरेमिक्स के लिए ईसीएमएस के अंतर्गत पहली बार दी गई मंजूरियां भी शामिल हैं। मंजूरियां नेस्ट आईसीईएलआर प्राइवेट लिमिटेड (मल्टी-लेयर पीसीबी), टीडीकॉनेक्स (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड (रिले), मॉडर्न ऑटोमोटिव्स लिमिटेड (हीट सिंक), वोल्टिक्स सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड (स्पेशलिटी सिरेमिक्स), इंडो एशिया कॉपर लिमिटेड (कॉपर फॉयल), टीएसीसी लिमिटेड (लिथियम-आयन सेल के लिए एनोड सामग्री), विद्युता मटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड (कैथोड एक्टिव मैटेरियल), एनरफोली एलएलपी (पॉलीप्रोपाइलीन फिल्म), सरफेस मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (कैमरा रिम), और कैपिटल गुड्स के लिए टीडीकॉनेक्स (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड (प्रिसिजन मोल्ड और टूलिंग), रॉकवेल ऑटोमेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (कैपिटल इक्विपमेंट हेतु पावर और कंट्रोल सिस्टम) और विप्रो परी रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड (फैक्ट्री ऑटोमेशन और सिस्टम इंटीग्रेशन से जुड़े कैपिटल इक्विपमेंट) को दी गई हैं। इनके साथ ईसीएमएस के तहत कुल 16 राज्यों में 34 उत्पादों से जुड़े 118 आवेदनों को मंजूरी मिल चुकी है, जिनसे 77,051 करोड़ रुपये के संभावित निवेश, 5,73,146 करोड़ रुपये के अनुमानित उत्पादन और 81,755 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन इंडिया 2.0 का मुख्य फोकस उपकरण, सामग्री, रसायन और गैसों पर होगा, और इसका लक्ष्य कम से कम तीन प्रमुख उपकरण निर्माताओं और पांच रसायन व गैस कंपनियों को भारत में लाना है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2333716

6 सरकार ने 2026-27 के लिए OMSS (D) के तहत चावल की बिक्री का लक्ष्य 25 LMT से दोगुना करके 50 LMT किया; 31 अक्टूबर 2026 तक ई-नीलामी के जरिए 25 LMT चावल पहले ही बेचा जा चुका है

Government doubles the OMSS (D) rice sale target for 2026-27 from 25 LMT to 50 LMT; 25 LMT already sold through e-auctions up to 31 October 2026

SSC • Banking • Railway • General

उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 6 नवंबर 2026 को बताया कि भारत सरकार ने 2026-27 के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम (घरेलू) [OMSS (D)] के तहत ई-नीलामी के जरिए बेचे जाने वाले चावल की मात्रा का लक्ष्य दोगुना कर दिया है, यानी इसे 25 LMT (लाख मीट्रिक टन) से बढ़ाकर 50 LMT कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 में 31 अक्टूबर 2026 तक OMSS (D) ई-नीलामी के माध्यम से निजी पार्टियों को कुल 25 LMT चावल बेचा गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह मात्रा 11 LMT थी। सरकार ने कहा कि वह खाद्य अनाजों, विशेष रूप से चावल की कीमतों पर कड़ी नज़र रख रही है, और इस कदम को घरेलू स्तर पर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने, कीमतों में स्थिरता बनाए रखने, जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उठाए गए उपायों में गिनाया। 6 नवंबर 2026 के एक आदेश के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी चेन वाले खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसर/मिल मालिकों को चावल और धान के अपने स्टॉक की जानकारी छह श्रेणियों - बासमती चावल, गैर-बासमती प्रीमियम चावल, गैर-बासमती चावल, उबला हुआ चावल (पारबॉइल्ड राइस), टूटा हुआ चावल और धान - में हर शुक्रवार को फूड स्टॉक पोर्टल पर देनी होगी; पोर्टल पर पंजीकृत न पाई जाने वाली या निर्धारित स्टॉक सीमा का उल्लंघन करने वाली इकाई के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। केंद्र ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना की राज्य सरकारों को आवश्यकतानुसार उचित नियंत्रण आदेशों के जरिए धान और चावल पर स्टॉक सीमा लागू करने की सहमति भी दी है; ये स्टॉक सीमाएं 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेंगी। इसके अलावा सरकार भारत चावल की बिक्री और उपलब्धता को पूरे देश में, विशेषकर दक्षिणी राज्यों में, बढ़ाने के लिए तीन एजेंसियों - नैफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार - को इसका अतिरिक्त आवंटन कर रही है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2333623

7 एनएचएआई ने चार लेन और उससे अधिक लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर बैरियर-रहित मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) टोलिंग के लिए टोल प्लाजा के डिजाइन और बुनियादी ढांचे को मानकीकृत करने के दिशानिर्देश जारी किए

NHAI issues guidelines to standardise the design and infrastructure of toll plazas for barrier-less Multi-Lane Free Flow (MLFF) tolling on four-lane and above National Highways

SSC • Railway • General

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 6 नवंबर 2026 को बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने बैरियर-रहित मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) टोलिंग प्रणाली को व्यापक रूप से अपनाने का मार्ग प्रशस्त करते हुए चार लेन और उससे अधिक लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा के डिजाइन और बुनियादी ढांचे को मानकीकृत करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। रिलीज़ के अनुसार ये दिशानिर्देश सुनिश्चित करेंगे कि आगामी और वर्तमान में जारी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं टोल बूथों पर वाहनों को रोके बिना एमएलएफएफ आधारित बाधा-मुक्त टोल संग्रह के लिए सुसज्जित हों; इस पहल का उद्देश्य यातायात कतारों और प्रतीक्षा समय को समाप्त करना और टोल प्लाजा पर ईंधन की खपत को कम करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग यात्राओं को सुरक्षित और अधिक निर्बाध बनाना है। नीति परिपत्र टोल प्लाजा लेआउट, लेन कॉन्फ़िगरेशन और टोल लेन की संख्या, गैंट्री, सड़क अवसंरचना, प्रकाश व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक परिवर्तनीय संदेश संकेत (वीएमएस) सहित सूचना पट्टिका, तथा प्रशासनिक भवन-सह-परिचालन और रखरखाव केंद्र जैसी सहायक सुविधाओं के लिए समान आवश्यकताएं निर्धारित करता है। भौतिक बाधाओं पर रुके बिना वाहनों से टोल लिए जाने के कारण टोल प्लाजा पर आवश्यक लेन की संख्या को पारंपरिक टोल प्लाजा की तुलना में युक्तिसंगत बनाया गया है। ये दिशानिर्देश सभी भावी और निर्माणाधीन परियोजनाओं पर लागू होंगे: विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) चरण की परियोजनाओं के दस्तावेजों में नया डिजाइन शामिल होगा, जबकि पहले से प्रदान की गई या निर्माणाधीन परियोजनाएं लागू संविदात्मक प्रावधानों के माध्यम से परिवर्तन अपनाएंगी, और एनएचएआई फील्ड कार्यालयों को आगामी परियोजनाओं में निर्धारित आवश्यकताओं को शामिल करने और वर्तमान में जारी परियोजनाओं में उन्हें अपनाने में सहायता का निर्देश दिया गया है। रिलीज़ में किसी टोल प्लाजा का नाम या इन दिशानिर्देशों के तहत एमएलएफएफ टोलिंग की कोई समय-सीमा नहीं दी गई है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2333654

8 डॉ. जितेंद्र सिंह: डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 5 के पहले पांच दिनों में लगभग 40 लाख प्रमाणपत्र बने, चेहरा प्रमाणीकरण अपनाने की दर बढ़कर लगभग 80 प्रतिशत हुई

Face authentication adoption surges to nearly 80 per cent as Digital Life Certificate Campaign 5 generates nearly 40 lakh certificates in its first five days: Dr Jitendra Singh

SSC • Banking • Railway • General

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 6 नवंबर 2026 को राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) अभियान 5 लॉन्च किया, जिसके पहले पांच दिनों में लगभग 40 लाख डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र बनाए गए, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह संख्या लगभग 25 लाख थी - यानी 60 प्रतिशत की वृद्धि। इसी अवधि के दौरान चेहरा प्रमाणीकरण अपनाने की दर 61 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 80 प्रतिशत हो गई, जिसे रिलीज़ प्रौद्योगिकी-सक्षम पेंशन सेवाओं में पेंशनभोगियों के बढ़ते विश्वास का संकेत बताती है। राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले साल बनाए गए 1.92 करोड़ डिजिटल जीवन प्रमाणपत्रों में से लगभग 1.17 करोड़ चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से बने थे; यह तकनीक पेंशनभोगियों को बैंकों या कार्यालयों में जाए बिना मोबाइल फोन से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र बनाने में सक्षम बनाती है। उन्होंने कहा कि लगभग 50 लाख कार्यरत कर्मचारियों के मुकाबले केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की संख्या अब लगभग 70 लाख तक पहुंच गई है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की सचिव सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा के अनुसार शिविरों के माध्यम से लगभग 3,000 स्थानों को कवर किया जा रहा है, और शिविरों में जाने में असमर्थ पेंशनभोगियों के लिए घर तक सेवाओं की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में एक सार-संग्रह पुस्तिका और राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान 4.0 का दस्तावेजीकरण करने वाली एक कॉफी टेबल ई-बुक जारी की गई।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2333632

9 दिल्ली में दैनिक औसत एक्यूआई 382 दर्ज किए जाने के बाद सीएक्यूएम ने पूरे एनसीआर में जीआरएपी का चरण-III तत्काल प्रभाव से लागू किया

CAQM invokes Stage-III of GRAP in the entire NCR with immediate effect as Delhi records a daily average AQI of 382

SSC • Railway • General

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 6 नवंबर 2026 को बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (जीआरएपी) संबंधी उप-समिति ने पूरे एनसीआर में मौजूदा जीआरएपी के चरण-III के तहत कार्ययोजना तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। 6 नवंबर 2026 को आयोजित अपनी बैठक में उप-समिति ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र की वायु गुणवत्ता की स्थिति के साथ-साथ आईएमडी/आईआईटीएम के पूर्वानुमानों की समीक्षा की। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के 6 नवंबर 2026 के दैनिक एक्यूआई बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में दैनिक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 382 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है; उप-समिति के अवलोकन के अनुसार इसका कारण प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के चलते प्रदूषकों का उचित फैलाव न हो पाना था, और आईएमडी/आईआईटीएम के पूर्वानुमानों के अनुसार आने वाले दिनों में एक्यूआई के 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचने की आशंका थी। चरण-III के तहत निर्धारित सभी उपायों को, पहले से लागू चरण-I और चरण-II के सभी उपायों के साथ-साथ, एनसीआर की सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना है, और एनसीआर के राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा डीपीसीसी सहित एजेंसियों को जीआरएपी के तीनों चरणों के तहत निर्धारित उपायों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। उप-समिति ने नागरिकों से चरण-I और चरण-II के साथ-साथ चरण-III के नागरिक चार्टर का पालन करने का आग्रह किया है: कम दूरी के लिए पैदल चलें या साइकिल का उपयोग करें, आवागमन के लिए कम प्रदूषणकारी परिवहन साधन चुनें, छोटी-छोटी यात्राओं को एक साथ मिलाएं और यात्राओं की संख्या कम करें, ऐसे निजी समारोहों को स्थगित करें जिनसे यातायात और खुले में रहने का जोखिम बढ़ता है, और ताप के लिए कोयले और लकड़ी का उपयोग न करें; मकान मालिक खुले में जैव-अवशेष, लकड़ी या नगरपालिका ठोस अपशिष्ट जलाने से बचने के लिए अपने सुरक्षा कर्मियों और अन्य कर्मचारियों को विद्युत हीटर उपलब्ध करा सकते हैं, और निर्देश दिए जाने पर प्राथमिक विद्यालयों में हाइब्रिड पद्धति और घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) अपनाया जाए। आयोग ने कहा कि वह स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहा है और वायु गुणवत्ता की नियमित समीक्षा करेगा। रिलीज़ में एजेंसियों के लिए चरण-III के उपायों की सूची नहीं दी गई है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2333904

आज का अभ्यास — 5 प्रश्न

प्र.1 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,814 करोड़ रुपये की 'महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय सहायता योजना' को मंजूरी दी है (जानकारी 4 नवंबर 2026 को दी गई)। यह योजना किन दो खनिजों के अयस्कों/मध्यवर्ती उत्पादों को उच्च शुद्धता वाले यौगिकों में प्रसंस्कृत करने का लक्ष्य रखती है?

(A) तांबा और जस्ता
(B) ग्रेफाइट और वैनेडियम
(C) दुर्लभ मृदा तत्व और टाइटेनियम
(D) लिथियम और निकेल

प्र.2 4-5 नवंबर 2026 को बेंगलुरु में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय टेबलटॉप अभ्यास 'वज्र-सैट' किस पशु रोग की तैयारी पर था?

(A) फुट-एंड-माउथ डिजीज (खुरपका और मुंहपका रोग) सीरोटाइप सैट-1
(B) अफ्रीकन स्वाइन फीवर
(C) एवियन इन्फ्लुएंजा (बर्ड फ्लू)
(D) लम्पी स्किन रोग

प्र.3 प्रधानमंत्री (5 नवंबर 2026) के अनुसार इस वर्ष के एशियाई पैरा खेलों में, जिनमें भारत के पदकों की संख्या 114 तक पहुंची, भारतीय खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीते?

(A) 30
(B) 36
(C) 29
(D) 34

प्र.4 रसायन और पेट्रोकेमिकल सेक्टर पर 7 नवंबर 2026 के PIB बैकग्राउंडर के अनुसार रसायनों के उत्पादन में दुनिया में भारत का स्थान क्या है?

(A) तीसरा सबसे बड़ा
(B) आठवाँ सबसे बड़ा
(C) दसवाँ सबसे बड़ा
(D) छठा सबसे बड़ा

प्र.5 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिदृश्य का एकीकृत दृश्य प्रदान करने वाले इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म 'इंडिया एसएंडटी स्कोरबोर्ड' का शुभारंभ 3 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में किस संस्था ने किया?

(A) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)
(B) अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ)
(C) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए)
(D) नीति आयोग

उत्तर: 1-(D) 2-(A) 3-(A) 4-(D) 5-(D)

रोज़ सुबह 7 बजे यही PDF Telegram पर: t.me/parikshasaathiapp — चैनल से जुड़ें और दोस्तों को भेजें

रोज़ का PDF: parikshasaathi.com/daily-pdf — सभी संस्करण: parikshasaathi.com/downloads/

वेबसाइट: parikshasaathi.com (हिंदी + English में 248 पाठ, रोज़ का करंट अफेयर्स, परीक्षा नोटिस)

ऐप: Pariksha Saathi — Free, Offline, SSC/Bank की पूरी तैयारी। प्रकाशक: Mahesh Srivastava, Founder. सामग्री आधिकारिक विज्ञप्तियों से AI की सहायता से तैयार; किसी विषय-विशेषज्ञ संपादक द्वारा समीक्षित नहीं। ग़लती दिखे तो parikshasaathi.com/contact/ पर बताएँ।